

खेल खेलने के जोखिम

The Perils of Playing Games

रणजॉय सेन

Ronojoy Sen

November 8, 2010

आम लोगों की आशंकाओं के विपरीत दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 14 अक्टूबर, 2010 को बिना किसी बड़े झंझट के खत्म हो गए. इन खेलों में इकहत्तर सदस्य देशों ने भाग लिया. राष्ट्रमंडल खेल चार साल में एक बार पूर्ववर्ती ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं. हो सकता है ये खेल 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेल और 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित सॉकर विश्व कप की तरह बहुत सफल नहीं हुए हों, लेकिन इन्हें असफल भी नहीं कहा जा सकता. लेकिन इनकी तथाकथित सफलता की आड़ में हम भारत में विशाल खेलकूद के आयोजन से संबद्ध अनेक मूलभूत कारणों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन से पूर्व जो तीखी बहस हुई थी, उससे दो महत्वपूर्ण तर्क उभर कर सामने आए थे. पहला तर्क पूर्व खेलकूद मंत्री मणिशंकर अय्यर ने ज़ोरदार ढंग से सामने रखा था. उनका मानना था कि खेलों पर इतनी भारी रकम खर्च करने के बजाय इसका उपयोग बच्चों को खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाना चाहिए या उन सामाजिक सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए, जिनकी भारत को सख्त ज़रूरत है.

दूसरा तर्क अर्ध-राष्ट्रिक है कि ये खेल भारत के उदीयमान शक्ति के रूप में उभरती हैसियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दूसरा तर्क खेलों को खेलकूद के मात्र आयोजन से संबद्ध नहीं मानता, बल्कि देश के खास तौर पर नई दिल्ली के मूलभूत ढाँचे को उन्नत करने से संबंधित मानता है. इस तर्क के अनुसार कुल बजट का एक छोटा-सा भाग ही खेलों पर सीधे खर्च किया गया है. शेष रकम दिल्ली मेट्रो के विस्तार, फ़्लाईओवर बनाने और हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने पर खर्च की गई है.

दोनों ही तर्कों में सत्य का एक अंश ज़रूर है, लेकिन अंततः दोनों ही तर्क दोषपूर्ण हैं. पहले तर्क में राष्ट्रमंडल खेल को या भारत के अंतरिक्ष मिशन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम या आयोजन को भारत के विकास के विरुद्ध माना गया है. इस तर्क के अनुसार भारत के विकास के लिए ये आवश्यक नहीं हैं. इस तर्क में इस प्रकार के विशाल आयोजनों से होने वाले उन तमाम लाभों और अतिरिक्त लाभों की पूरी तरह अनदेखी की गई है. दूसरे तर्क में भारतीय शहरों के मूलभूत ढाँचे को विकसित करने के लिए खेलकूद के कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता की अनदेखी की गई है.

किसी विकासशील देश में विशाल खेलकूद का आयोजन करने का तर्क यही है कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ना चाहिए। कुछ लोग यह समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद के आयोजनों से मेज़बान देश को कोई लाभ नहीं होता और इससे केवल आईओसी या फीफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की संस्थाओं की तिजोरी ही भरती है। 1984 में आयोजित लॉस एन्जेल्स के खेलों से पूर्व ओलंपिक का खेल मेज़बान देश के लिए घाटे का सौदा ही रहा है, लेकिन लॉस एन्जेल्स के खेलों के बाद इसमें चमत्कारी परिवर्तन हुआ और उसके बाद ओलंपिक खेल मेज़बान देश के लिए एक व्यावसायिक कार्य बन गया और साथ ही मौजूदा बुनियादी ढाँचे का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। लॉस एन्जेल्स के खेलों से \$232.5 मिलियन डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ, जबकि इससे आठ साल पहले मॉन्ट्रियल में आयोजित ओलंपिक खेलों से उस पर \$1.5 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया था। यद्यपि भारत जैसे देशों पर लॉस एन्जेल्स का मॉडल लागू नहीं होता, जहाँ सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेलकूदों के आयोजन में पूरा सहयोग करती है और अनेक एजेन्सियाँ भी इसमें शामिल रहती हैं।

खेलकूद के अधिकांश आयोजनों में खर्च का बजट डगमगा ही जाता है, इसलिए दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल के खेलों का बजट यदि डगमगाया है तो यह कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2007 में खेलों के लिए \$766 मिलियन डॉलर का बजट मंजूर किया था। जब तक खेल शुरू हुए तब तक इसकी लागत बढ़कर \$8.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई थी। इसमें केवल खेलों पर होने वाला खर्च ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढाँचे का सुधार भी शामिल था। कुछ अनुमानों के अनुसार यह लागत बढ़कर \$15 बिलियन डॉलर हो गई थी।

जिन स्थानों पर बुनियादी ढाँचे का काम शुरूआत से शुरू होना था, वहाँ बजट बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ जाती है। जब अमरीका ने 1994 में सॉकर विश्व कप का आयोजन किया था तो उसने स्टेडियम पर \$30 मिलियन डॉलर से भी कम खर्च किया था, जबकि दक्षिण कोरिया ने 2002 में विश्व कप के आयोजन के समय जापान के साथ मिलकर मेज़बानी करते समय \$2 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन तमाम विकासशील देशों के लिए यह बड़ी चुनौती है, जहाँ विशाल पैमाने पर खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा मौजूद नहीं है। यद्यपि भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उसे या तो व्यापक तौर पर स्टेडियमों का पुनर्निर्माण करना पड़ा या नए स्टेडियमों का निर्माण करना पड़ा। उदाहरण के लिए खेलों के मुख्य स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पुनर्निर्माण पर \$200 मिलियन डॉलर खर्च किए गए, जबकि 1982 में इसके निर्माण पर कुल \$70 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। इसके विपरीत ग्लासगो में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन स्थल, सेल्टिक पार्क, जो इस समय चालू हालत में है, पर खेलों से पूर्व थोड़ी-बहुत मरम्मत का ही काम होगा।

खेलकूद से संबंधित आयोजनों के लिए आवश्यक राजस्व अर्जन के लिए टेलीविज़न अधिकार, प्रवर्तन (स्पॉन्सरशिप), टिकट बिक्री और विपणन आम स्रोत होते हैं। यद्यपि सही आँकड़े मुश्किल से ही मिल

पाएँगे, फिर भी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल के खेलों के प्रति प्रवर्तक (स्पॉन्सर) और दर्शक दोनों ही अन्यमनस्क बने रहे, क्योंकि एक आयोजन की तरह ब्रांड मूल्य के रूप में राष्ट्रमंडल-खेलों की तुलना ओलंपिक या सॉकर विश्व कप से नहीं की जा सकती. हज़ारों टिकट अनबिके रह गए और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर कोई और कंपनी खेलों पर पैसा लगाने को तैयार नहीं थी. इस स्थिति में तब ज़रूर कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा, जब भारत ने बहुत-से पदक जीतने शुरू कर दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

वस्तुतः इस प्रकार के खेलकूदों के विशाल आयोजनों से कुछ और लाभ भी होते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत तुलनापत्र में नहीं दिखाया जा सकता. उदाहरण के तौर पर मन्चेस्टर में सन् 2002 में आयोजित राष्ट्रमंडल के खेलों के दो प्रमुख उद्देश्य थे: पूर्वी मन्चेस्टर, जो एक ज़माने में औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, का पुनर्निर्माण करना और क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना. उसके बाद सन् 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक खेलों का प्रमुख उद्देश्य था, शहर की छवि को उभारना और पर्यटन को बढ़ावा देना. सन् 2012 के लंदन के खेलों का उद्देश्य भी शहर के गरीब और अपराधी तत्वों से भरे इलाकों का विकास करना ही है. किसी भी दृष्टि से नई दिल्ली को ऐसा कोई भी लाभ नहीं मिला. इतना ही नहीं, खेलों की अव्यवस्था पूर्ण स्थिति के कारण भारत की प्रतिष्ठा भी दाँव पर लग गई थी. साथ ही जाँच से पता चला है कि खेलों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए हज़ारों गरीब परिवारों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया था और कामगारों को उचित मज़दूरी और ज़िंदा रहने लायक स्थितियों से भी वंचित रखा गया..

राष्ट्रमंडल खेलों से दो लाभ तो हुए: शहरी बुनियादी ढाँचा और खेल की विरासत. खेलों के बजट का सबसे अधिक पैसा दिल्ली के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में लगा. यही उसका पहला लाभ है. सन् 1982 में भी नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के समय भी अधिकांश पैसा सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डे को सुधारने और बिजली उत्पादन पर ही लगाया गया था. परंतु सवाल फिर भी उठता है कि खेलों से प्रेरित शहरी विकास अधिक दक्षता के साथ क्यों नहीं किया गया. सरकारी लेखा-परीक्षा और मीडिया की जाँच से पता चलता है कि दिल्ली को खेलों के लिए तैयार करने में जो जल्दबाजी की गई उसके लिए जवाबदारी किसकी है और इस जल्दबाजी में पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया गया. पिछले साल भर में केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारत के नियंत्रक व महा लेखा निरीक्षक जैसी भारत सरकार की जाँच एजेंसियों और मीडिया ने ठेके जारी करने, निर्माण कार्य की लचर निगरानी और राजस्व अर्जन के मॉडल से जुड़े कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रचारित मामला तो यही था कि टॉयलेट रोल्लस का बिल \$88 डॉलर प्रति रोल आया है.

जहाँ तक खेलकूद की विरासत का सवाल है, इसका सीधा उदाहरण तो 1982 के एशियाई खेल हैं कि कैसे विशाल आयोजन भी खेलकूद को फलने-फूलने और विकसित करने में कोई योगदान नहीं कर सकते. एशियाई खेल के खत्म होने के बाद भी खेलकूद का बुनियादी ढाँचा बेकार और उजाड़ पड़ा रहा.

भारत में ही नहीं,भारत के बाहर भी ओलंपिक के मेज़बान शहरों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब एक बार खेल खत्म होने के बाद स्टेडियम उजाड़ पड़े रहे. यह तो साफ़ ही है कि एशियाई खेलों के खत्म होने के तुरंत बाद भी खेलकूद के लिए भारत के निष्पादन में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

यह खुशी की बात है कि राष्ट्रमंडल के खेलों की रौनक खत्म होने के बाद भी सरकार खेल की संगठन समिति और अन्य सरकारी एजेन्सियों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के जो आरोप लगे हैं,उन्हें भूली नहीं है. एक वरिष्ठ नौकरशाह की अध्यक्षता में गठित एक समिति सभी अनियमितताओं की जाँच कर रही है और यह समिति जनवरी, 2011 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. यद्यपि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें इससे एक बड़ा सबक यह सीखना है कि खेलकूद के बड़े आयोजन भारत जैसे देशों के लायक नहीं हैं. यह एक ऐसी बात है जिसे ओलंपिक जैसे बड़े खेलों के आयोजन के लिए बोली बोलने से पहले हमें भूलना नहीं चाहिए.

रणजॉय सेन सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में विज़िटिंग अनुसंधान फ़ेलो हैं.

हिंदी अनुवाद: विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार

<malhotravk@hotmail.com>